ऊर्जा संरक्षण सप्ताह के अवसर पर माननीय प्रबंध संचालक महोदय का संदेश

आज 14 दिसंबर ऊर्जा संरक्षण दिवस के शुभ अवसर पर ऊर्जा की बचत हेतु मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आव्हान करता हूं एवं ऊर्जा का मितव्ययी उपयोग करने हेतु आग्रह करता हूं।

ऊर्जा संरक्षण के लिये दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्पित क्रियान्वयन की आवश्यकता है। दिन में सूर्य के प्रकाश का अधिकतम उपयोग, भोजनावकाश के दौरान एवं कमरे से बाहर जाते समय पंखे, लाईट, एसी उपकरणों को बंद रखना, बल्ब और ट्यूबलाइट के स्थान पर एल.ई.डी. का उपयोग बिजली की खपत में पर्याप्त कमी लाता है। उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर हम सभी को ऊर्जा संरक्षण करते हुये ऊर्जा का बेहतर उपयोग अधिक जरूरतमंद क्षेत्रों में किये जाने हेतु सक्रिय योगदान देना चाहिये।

भारत सरकार द्वारा ''**उजाला कार्यक्रम**'' के अंतर्गत एलईडी बल्ब पूरे देश में वितरित किये जा रहे हैं एवं साधारण बल्बों तथा सीएफएल के स्थान पर लगाये जा रहे हैं। एलईडी बल्ब की संचालन अवधि 25 से 30 हजार घण्टे होती है। इस योजना में दिनांक 17 नवंबर-2016 की स्थिति में राष्ट्रीय उजाला डैश बोर्ड के अनुसार 17.87 करोड़ एलईडी बल्ब वितरित किये जा चुके हैं एवं इनके उपयोग से 2,32,03,045 एम.डब्ल्यू.एच. प्रतिवर्ष बिजली की बचत हो रही है एवं प्रतिवर्ष 9,281 करोड़ रूपये की बचत होगी तथा ऊर्जा की मांग में 4645 मेगावॉट की कमी हुई है। साथ ही साथ कार्बन डायऑक्साईड का उत्सर्जन प्रतिवर्ष 1,87,94,467 टन कम हो रहा है। जैसे-जैसे एलईडी बल्ब की संख्या बढ़ेगी उक्त आंकड़े बदलते जाएंगे।

ऊर्जा बचत के क्षेत्र में भारत सरकार का ''**उजाला कार्यक्रम**'' क्रांति के रूप में कार्य कर रहा है एवं इसमें हर एक व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उजाला कार्यक्रम की संपूर्ण जानकारी उजाला डैश बोर्ड की वेबसाईट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू.डीईएलपी.इन पर उपलब्ध है। उजाला कार्यक्रम से आम उपभोक्ताओं का बिजली का बिल भी कम होगा एवं पर्यावरण की भी रक्षा की जा सकेगी। इसी तारतम्य में हमारे प्रदेश में भी 6 माह के अल्प समय में 3 करोड़ एलईडी बल्ब लगाने का लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय उजाला डैश बोर्ड के अनुसार अभी तक हमारे प्रदेश में 17 नवंबर-2016 की स्थिति में 87,50,316 एलईडी बल्ब साधारण बल्ब की जगह लगाये जा चुके हैं जिससे 11,36,377 एम.डब्ल्यू.एच. प्रतिवर्ष ऊर्जा की बचत की जा चुकी है एवं प्रतिवर्ष 455 करोड़ रूपये की बचत हो रही है तथा 228 मेगावॉट पीक विद्युत की मांग में कमी आयी है। साथ ही साथ प्रतिवर्ष 9,20,466 टन कार्बन डायऑक्साईड का उत्सर्जन कम हो रहा है। इस प्रकार बची हुई ऊर्जा से दूसरे घरों को रोशन किया जा रहा है।

देश में सौर ऊर्जा से 70 से 210 गीगावॉट उत्पादन की संभावना है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के अंतर्गत भारत सरकार ने 2022 तक सोलर रूफ टॉप पैनल की 40 हजार मेगावॉट (40 गीगावॉट) क्षमता ग्रिड से जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्षों में (2014-15 से 2018-19 तक) 21 राज्यों में 27 बड़े सोलर पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है, जिनकी कुल क्षमता 18418 मेगावॉट है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत मध्यप्रदेश में भी 5 वर्षों में सौर ऊर्जा पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी तारतम्य में 750 मेगावॉट अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क 1400 हेक्टेयर क्षेत्रफल रीवा के पास ग्राम गुढ़ में प्रस्तावित है एवं इसी प्रकार कुल 2000 मेगावॉट क्षमता के सोलर पार्क नीमच, आगर, मंदसौर, शाजापुर, राजगढ़, छतरपुर तथा मुरैना में 6000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रस्तावित है। भारत सरकार द्वारा सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों/शैक्षणिक संस्थानों की इमारतों पर सोलर रूफ टॉप पैनल लगाये जा रहे हैं। सौर ऊर्जा मिशन के पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार के गैर-परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 100 किलोवॉट से 500 किलोवॉट के रूफ टॉप सोलर पैनल की स्थापना लगातार की जा रही है। इस कार्य में सोलर एनर्जी कार्पोरेशन ऑफ इंडिया को भारत सरकार द्वारा सौर ऊर्जा के प्रचार-प्रसार हेतु नोडल एजेंसी के रूप में उपयोग किया जा रहा है। इस हेतु मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर ऊर्जा के विस्तार एवं संधारण हेतु ''**सूर्यमित्र**'' नियुक्त किये जा रहे हैं एवं ''**सूर्यमित्र**'' एप का भी शुभारंभ किया गया है। भवन निर्माण में अक्षय ऊर्जा का उपयोग कैसे किया जाये इस हेतु ''**अटल अक्षय ऊर्जा**'' भवन के निर्माण हेतु नई दिल्ली में आधारशिला माननीय केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा रखी जा चुकी है जो कि अपने आप में ऐतिहासिक भवन, गैर-परंपरागत ऊर्जा क्रांति का उत्तम उदाहरण होगा।

मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने भी अपने स्तर पर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण प्रयास किये हैं एवं हमारे इस प्रयास को विभिन्न स्तरों पर मान्यता भी मिली है। इसी कड़ी में कंपनी द्वारा प्रदेश में स्थापित हो रहे नवीन उच्चदाब उपकेंद्रों में प्रकाश व्यवस्था हेतु एलईडी बल्बों का उपयोग किया जा रहा है एवं पूर्व से ही विद्यमान अति उच्चदाब उपकेंद्रों में सीएफएल एवं साधारण बल्ब के स्थान पर क्रमबद्ध तरीके से एलईडी बल्ब लगाने का कार्य जारी है। कंपनी द्वारा नव निर्माणाधीन अति-उच्चदाब उपकेन्द्रों पर भी रूफटाप सोलर पैनल का प्रावधान किया जा रहा है । आइये हम सब मिलकर ऊर्जा संरक्षण की दिशा में प्रयास जारी रखें।

(रवि सेठी)
प्रबंध संचालक
म.प्र.पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी लिमि., जबलपुर